



## International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 2, Issue 7, pp 170-181, July 2025

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में बदलाव पर एक विश्लेषणात्मक शोध

**बलदाऊ सिंह श्याम**

पद : सहायक शिक्षक

विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।

विद्यालय: शासकीय प्राथमिक शाला, जमुनाही तिलकडीह, विकास खंड: कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

शिक्षा: एम.ए. (हिन्दी), डी.एड. पीजीडीसीए,

मेल आईडी: [baldausingh75@gmail.com](mailto:baldausingh75@gmail.com)

सार-

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, देश के शैक्षिक दर्शन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य समग्र, लचीला और बहु-विषयक शिक्षण को बढ़ावा देना है। समृद्ध आदिवासी विरासत और सामाजिक-आर्थिक विविधता वाले राज्य छत्तीसगढ़ ने शैक्षिक असमानताओं को पाटने और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के उद्देश्य से एनईपी कार्यान्वयन की यात्रा शुरू की। यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ में एनईपी 2020 को अपनाने के प्रक्षेपवक्र की खोज करता है, 2020 से लेकर 2025-26 के वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक स्कूली शिक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह यात्रा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के नेतृत्व में राज्य-स्तरीय अभिविन्यास कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम संरक्षण कार्यशालाओं के साथ शुरू हुई। 2022 तक, छत्तीसगढ़ ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन), शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण में पायलट कार्यक्रम शुरू किए थे। राज्य के सक्रिय दृष्टिकोण में पाठ्यपुस्तकों में आदिवासी ज्ञान प्रणालियों को शामिल करना, स्कूली पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 मॉडल में पुनर्गठित करना और कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करना शामिल है। 2023-24 सत्र में कक्षा 3 और 6 के लिए संशोधित पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत, योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समग्र प्रगति कार्ड का कार्यान्वयन देखा गया। 2025-26 तक, छत्तीसगढ़ ने समावेशी शिक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और बहुभाषी शिक्षाशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी जिलों में इन सुधारों को बढ़ाया था। यह अध्ययन मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें यूडीआईएसई+ रिपोर्ट से मात्रात्मक डेटा और शिक्षकों, प्रशासकों और छात्रों के साथ साक्षात्कार से गुणात्मक अंतर्दृष्टि को मिलाया गया है। निष्कर्ष छात्र जुड़ाव, शिक्षक सशक्तिकरण और पाठ्यक्रम प्रासंगिकता में महत्वपूर्ण सुधार दिखाते हैं। हालांकि, दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच, शिक्षक क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं। पेपर का निष्कर्ष है कि एनईपी 2020 ने छत्तीसगढ़ में शैक्षिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत नींव रखी है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए निरंतर निवेश, स्थानीय नवाचार और निरंतर

निगरानी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ मॉडल अन्य राज्यों के लिए विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में एनईपी कार्यान्वयन की जटिलताओं को समझने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है।

कीवर्ड: एनईपी 2020, छत्तीसगढ़, स्कूली शिक्षा, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, मूलभूत साक्षरता, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बहुभाषावाद ।

### परिचय : छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा का विकास (2000-2020)

जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर, 2000 को एक अलग राज्य बनाया गया, तो इसे कई गहरी चुनौतियों का सामना करने वाली स्कूली शिक्षा प्रणाली वरासत में मिली। इस क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा तक सीमा तक पहुँच थी, खासकर आदिवासी बहुल जिलों में, और बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की उपलब्धता और साक्षरता में बहुत बड़ी खाई थी। शिक्षा को विकास के एक आधारभूत स्तंभ के रूप में मान्यता देते हुए, नवगठित राज्य ने पहुँच का विस्तार करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई तरह की पहल की, जिससे दीर्घकालिक सुधार की नींव रखी गई। राज्य बनने के बाद के पहले दशक में, छत्तीसगढ़ ने नामांकन बढ़ाने और स्कूली शिक्षा तक भौतिक पहुँच बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए हजारों नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए। शिक्षक मर्यादा (स्थानीय शिक्षकों) की भर्ती ने शिक्षण रिक्तियों को भरने में मदद की, जबकि मंड-डे मील योजना की शुरुआत ने पोषण संबंधी चिंताओं को दूर करके अधिक बच्चों को कक्षाओं में आकर्षित किया। इन प्रयासों के बावजूद, शिक्षा की गुणवत्ता असमान रही, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र प्रतियोगिता और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के परिणामों में व्यापक मुद्दे थे। दूसरे दशक में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा निर्देशित अधिक संरचित सुधारों का उदय हुआ। छत्तीसगढ़ ने अपने स्कूल के बुनियादी ढाँचे को RTE मानदंडों के अनुरूप बनाकर, सरकारी स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय, स्वच्छ पेयजल और चारदीवारी सुनिश्चित करके जवाब दिया। शासन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई, जबकि लड़कियों, वकलांग बच्चों और हाशिए की पृष्ठभूमि के बच्चों का समर्थन करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप शुरू किए गए। बालिका शिक्षा कार्यक्रम और स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स जैसी राज्य द्वारा संचालित पहलों ने समान पहुँच और भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। 2015 और 2020 के बीच, छत्तीसगढ़ का ध्यान गुणवत्ता वृद्धि और शिक्षण सुधार की ओर चला गया। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में सीखने की कमी को दूर करने के लिए गुणवत्ता अभियान (गुणवत्ता अभियान) जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। शिक्षक प्रशिक्षण को तीव्र किया गया, तथा स्मार्ट कक्षाओं और टैबलेट वितरण जैसी पहलों के माध्यम से चुनिंदा विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण उपकरणों को पैर जमाना शुरू हुआ। एक उल्लेखनीय पहल स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों के छात्रों को आधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ सस्ती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। पाठ्यक्रम में धीरे-धीरे NCERT मानकों के साथ संरेखण देखा जाने लगा, तथा राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने क्षेत्रीय ज्ञान और आदिवासी संस्कृति को शामिल करने वाली पाठ्यपुस्तकों को डिजाइन करने में सक्रिय भूमिका निभाई। 2020 तक, छत्तीसगढ़ ने अधिक समावेशी और सुलभ स्कूली शिक्षा प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। फिर भी चुनौतियाँ बनी रहीं, विशेष रूप से छात्र सीखने के परिणामों, आंतरिक क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम में 21वीं सदी के कौशल को एकीकृत करने के संदर्भ में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा समय पर हुई। समय, बहु-वर्षीय और लचीली शिक्षा पर जोर देने के साथ, NEP राज्य की कई मौजूदा प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ ने इस नीति को अपनाने के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया है, मूलभूत साक्षरता पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, नई पाठ्यचर्या संरचना में बदलाव की शुरुआत की है और मातृभाषा में शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए रणनीतियों का मसौदा तैयार किया है। यह बीस साल की यात्रा छत्तीसगढ़ की एक उत्तरदायी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। NEP 2020 तक के सुधार केवल प्रशासनिक समायोजन नहीं थे - वे बच्चों के

सीखने, शिक्षकों के पढ़ाने और समुदायों के शिक्षा से जुड़ने के तरीके को बदलने की दिशा में एक कदम था। नींव रखी जा चुकी थी, और अब NEP 2020 द्वारा शुरू किए जाने वाले गहरे संरचनात्मक और पाठ्यचर्या परिवर्तनों के लिए मंच तैयार था।

### एनईपी 2020 और पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तुलनात्मक समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की शुरुआत के साथ भारतीय शिक्षा के परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है, जिसने लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 की जगह ली है, जिसे 1992 में थोड़ा संशोधित किया गया था। यह बदलाव 34 वर्षों के अंतराल के बाद आया है, जिसके दौरान भारत ने महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक विकास देखा। एनईपी 2020 एक दूरदर्शी, समग्र और समावेशी ढांचा है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की मांगों के साथ जोड़ना है। इसके विपरीत, एनपीई 1986 अपने समय का एक उत्पाद था, जो एक नई उदार अर्थव्यवस्था में पहुंच, समानता और शैक्षिक अवसरों के विस्तार पर केंद्रित था।

एनईपी 2020 द्वारा शुरू किए गए सबसे ज्यादा दिखने वाले बदलावों में से एक स्कूली शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन है। एनपीई 1986 के पारंपरिक 10+2 मॉडल को एक नए 5+3+3+4 पाठ्यचर्या ढांचे से बदल दिया गया है। यह मॉडल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों से मेल खाता है: पाँच साल का आधारभूत चरण (जिसमें प्री-प्राइमरी और ग्रेड 1-2 के तीन साल शामिल हैं), तीन साल का प्रारंभिक चरण (ग्रेड 3-5), तीन साल का मध्य चरण (ग्रेड 6-8), और चार साल का माध्यमिक चरण (ग्रेड 9-12)। यह बदलाव प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के महत्व को पहचानता है, जो 1986 की नीति में काफी हद तक अनुपस्थित था। एनईपी 2020 ईसीसीई को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करता है, जो आधारभूत वर्षों में खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित सीखने पर जोर देता है।

इसके विपरीत, एनपीई 1986 ने प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड 8 तक) को सार्वभौमिक बनाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया और औपचारिक रूप से इसके ढांचे के भीतर पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को शामिल नहीं किया। प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच बढ़ाने, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, और ड्रॉपआउट दरों को कम करने पर जोर दिया गया था। जबकि ये लक्ष्य उस समय के लिए महत्वपूर्ण थे, नीति में प्रारंभिक बचपन के विकास और सीखने के परिणामों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की सूक्ष्म समझ का अभाव था। एनईपी 2020 पाठ्यक्रम और शिक्षण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। यह अधिक समग्र, एकीकृत, आनंददायक और आकर्षक सीखने के अनुभव की वकालत करता है। नीति रटने, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान पर वैचारिक समझ पर जोर देती है। यह शिक्षणक धाराओं (कला, विज्ञान, वाणिज्य), पाठ्यचर्या और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों और व्यावसायिक और शिक्षणक ट्रेक के बीच कठोर अलगाव को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। छात्रों को विषय चुनने में लचीलापन बढ़ेगा, जिससे बहु-विषयक सीखने की अनुमति मिलेगी। इसके विपरीत, एनपीई 1986 ने पाठ्यक्रम के लिए अधिक कठोर और खंडित दृष्टिकोण का पालन किया। इसका ध्यान विषय-वस्तु-भारी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक-केंद्रित शिक्षण और उच्च-दांव वाली परीक्षाओं पर था। हालाँकि नीति ने व्यावसायिक शिक्षा और मूल्य-आधारित शिक्षण की आवश्यकता को पहचाना, लेकिन इसका कार्यान्वयन सीमित और खंडित रहा। शिक्षणक पद्धतियाँ काफी हद तक शिक्षक-केंद्रित थीं, जिनमें अनुभवात्मक या पूछताछ-आधारित शिक्षण के लिए सीमित गुंजाइश थी।

एनईपी 2020 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार है। नीति में नियमित, योग्यता-आधारित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन में बदलाव का प्रस्ताव है, जो विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च-क्रम कौशल का परीक्षण करता है। 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत और एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) की स्थापना का उद्देश्य देश भर में मूल्यांकन की गुणवत्ता को मानकीकृत और बेहतर बनाना है। इसके विपरीत, एनपीई 1986 ने मूल्यांकन के प्राथमिक तरीके के रूप में वार्षिक परीक्षाओं पर बहुत अधिक भरोसा किया। ये परीक्षाएँ अक्सर रटने को बढ़ावा देती हैं और छात्रों में अनावश्यक तनाव पैदा

करती हैं। नीति ने मूल्यांकन प्रथाओं में कसी भी प्रणालीगत सुधार का प्रस्ताव नहीं दिया, जिससे को चंग और परीक्षा-केंद्रित शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

एनईपी 2020 बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह अनुशंसा करता है कि कम से कम ग्रेड 5 तक - और अधिमानतः ग्रेड 8 तक - शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। नीति तीन-भाषा सूत्र का भी समर्थन करती है, छात्रों को तीन भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएँ शामिल हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भाषाई वृद्धता को संरक्षित करना और बच्चे को परिचित भाषा में पढ़ाकर सीखने के परिणामों में सुधार करना है। एनपीई 1986 ने भी तीन-भाषा सूत्र का समर्थन किया, लेकिन राज्यों में इसके समान कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, नीति ने क्षेत्रीय भाषाओं को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप प्रदान नहीं किया, और कई निजी और शहरी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के पसंदीदा माध्यम के रूप में हावी रही।

एनईपी 2020 उच्च शिक्षा प्रणाली में पूर्ण बदलाव की परिकल्पना करता है। इसमें बहुवर्षीय शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना, क्रेडिट हस्तांतरण के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का निर्माण और डीजी कार्यक्रमों में कई प्रवेश और विकास विकल्पों की शुरुआत का प्रस्ताव है। नीति का उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50% तक बढ़ाना है और समग्र, लचीली और बहुवर्षीय शिक्षा पर जोर देता है। इसके विपरीत, एनपीई 1986 ने उच्च शिक्षा को मुख्य रूप से विस्तार और पहुँच के लक्ष्यों के माध्यम से देखा। जबकि इसने गुणवत्ता सुधार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की वकालत की, नीति में संस्थागत स्वायत्तता, अंतः-वर्षीय सीखने या अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए व्यापक दृष्टिकोण का अभाव था। नियामक ढांचा खंडित रहा, जिसमें कई निकाय उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करते थे।

एनईपी 2020 शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली की आधारशिला के रूप में मान्यता देता है। यह चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करता है। 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में डीजी को लागू करने और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से निरंतर व्यावसायिक विकास पर जोर दिया गया है। नीति में मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना और एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रणाली के निर्माण का भी आह्वान किया गया है। NPE 1986 ने शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व को भी स्वीकार किया और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, कार्यान्वयन असमान था, और कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पुराने और कक्षा की वास्तविकताओं से कटे हुए थे। नीति ने शिक्षक प्रेरणा, जवाबदेही या कैरियर की प्रगति के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। NEP 2020 समानता और समावेशन पर जोर देता है। यह वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ), एक लिंग समावेशन कोष और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) के लिए लक्षित हस्तक्षेप का प्रस्ताव करता है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमताएँ कुछ भी हों। एन.पी.ई. 1986 का उद्देश्य शिक्षा में असमानताओं को कम करना था, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और अन्य हाशिए के समुदायों के लिए। हालाँकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तंत्र दायरे और प्रभावशीलता में सीमित थे। एन.ई.पी. 2020 इन नीतियों पर अधिक डेटा-संचालित और लक्षित दृष्टिकोण के साथ निर्माण करता है।

एन.ई.पी. 2020 शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के एकीकरण की कल्पना करता है। यह विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुवर्धाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी मंच (एन.ई.टी.एफ.) की स्थापना का प्रस्ताव करता है। नीति विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शिक्षण, सीखने, मूल्यांकन और प्रशासन के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। एन.पी.ई. 1986, जो डिजिटल युग से पहले तैयार किया गया था, ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का अनुमान नहीं लगाया था। हालाँकि इसमें दृश्य-श्रव्य सहायता और दूरस्थ शिक्षा के उपयोग का उल्लेख किया गया था, लेकिन नीति में पहुँच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की व्यापक रणनीति का अभाव था।

NEP 2020 शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक “हल्का लेकन सख्त” वनियामक ढांचा प्रस्तावित करता है। यह वनियमन, मान्यता, वन पोषण और शैक्षणिक मानकों के लिए चार कार्यक्षेत्रों के साथ एक एकल व्यापक निकाय- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के निर्माण की अनुशंसा करता है। इसका उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करना और संस्थागत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसके वपरीत, NPE 1986 एक अधिक केंद्रीकृत और कठोर वनियामक संरचना के भीतर संचालित होता था। ओवरलैपिंग कार्यों वाली कई एजेंसियों के कारण अक्सर अक्षमता और समन्वय की कमी होती थी। संस्थागत स्वायत्तता सीमित थी, और अत्यधिक वनियमन द्वारा नवाचार को रोक दिया गया था।

शायद NEP 2020 की सबसे परिभाषित विशेषता इसका वैश्विक दृष्टिकोण है। नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने की आकांक्षा रखती है। यह छात्र और संकाय आदान-प्रदान, अनुसंधान सहयोग और भारत में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के प्रवेश के माध्यम से शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करती है। एनपीई 1986, अपने समय के लिए प्रगतिशील होने के बावजूद, काफी हद तक अंतर्मुखी थी। इसका प्राथमिक ध्यान राष्ट्र निर्माण और निरक्षरता, लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी घरेलू चुनौतियों का समाधान करने पर था। नीति ने छात्रों को वैश्वीकृत दुनिया की मांगों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया। संक्षेप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली की एक साहसिक और व्यापक पुनर्कल्पना का प्रतिनिधित्व करती है। यह पछली नीति की कई कमियों को संबोधित करती है और शिक्षा को तेजी से बदलती दुनिया की जरूरतों के साथ जोड़ती है। जबकि एनपीई 1986 ने पहुंच का विस्तार करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए आधार तैयार किया, एनपीई 2020 गुणवत्ता, लचीलेपन और भविष्य की तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस नींव पर निर्माण करती है। हालांकि, एनपीई 2020 का भविष्य प्रभावी क्रयान्वयन, पर्याप्त वन पोषण और निरंतर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। अगर इसे अच्छी तरह से क्रयान्वित किया जाता है, तो इसमें सीखने के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता है जो समावेशी, अभिनव और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी है।

### छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा में बदलाव: NEP 2020 क्रांति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का क्रयान्वयन भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका उद्देश्य सीखने को अधिक समग्र, लचीला और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। आदिवासी संस्कृति और विविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ में, NEP 2020 को अपनाने से स्कूली शिक्षा परिदृश्य में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। समावेशी विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता के साथ, इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए पहले से ही कई सुधार चल रहे हैं।

NEP 2020 द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक पारंपरिक 10+2 मॉडल से नए 5+3+3+4 पैटर्न में शैक्षणिक ढांचे का पुनर्गठन है। इस प्रणाली में आधारभूत चरण (आयु 3-8), प्रारंभिक चरण (8-11), मध्य चरण (11-14) और माध्यमिक चरण (14-18) शामिल हैं। छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक स्तर पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस संरचना को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। आधारभूत चरण में खेल-आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जबकि बाद के चरणों में धीरे-धीरे अधिक अमूर्त सोच, अनुभवात्मक शिक्षा और अंतःविषय दृष्टिकोण पेश किए जाते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य रटने की शिक्षा को खोज और आलोचनात्मक सोच से बदलना है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने कक्षा 3 और 6 के लिए पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया है ताकि वे NEP 2020 के लक्ष्यों के साथ संरेखित हो सकें, जिसमें गतिविधि-आधारित शिक्षा और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग पर जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम में सुधार का एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहलू स्थानीय आदिवासी ज्ञान, संस्कृति और संदर्भ का एकीकरण है। पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय सामग्री को शामिल करके, छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया में प्रासंगिकता और पहचान मिलने की अधिक संभावना है। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में प्रोजेक्ट-आधारित असाइनमेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि अवधारणाएँ केवल याद नहीं बल्कि समझी और लागू की जाएँ। NEP 2020 के योग्यता-आधारित

ढांचे के अनुरूप, राज्य की मूल्यांकन प्रथाएँ मानकीकृत परीक्षाओं से रचनात्मक, व्यक्तिगत मूल्यांकन की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ समग्र प्रगति कार्ड पेश कर रहा है जो न केवल अकादमिक प्रदर्शन बल्कि सह-पाठ्यचर्या भागीदारी और भावनात्मक कल्याण का भी मूल्यांकन करता है। महामारी के दौरान सीखने के अंतराल से प्रभावित छात्रों के लिए, विशेष रूप से ग्रेड के बीच सुचारु शैक्षणिक संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज कोर्स लागू किए गए हैं। लक्ष्य ऐसे शिक्षार्थियों को तैयार करना है जो गंभीर रूप से सोच सकें, रचनात्मक रूप से समस्याओं को हल कर सकें और अभिन्न चुनौतियों के लिए लचीले ढंग से अनुकूलन कर सकें।

#### संरचनात्मक 5+3+3+4 मॉडल-

सबसे अधिक दिखाई देने वाले बदलावों में से एक है पारंपरिक 10+2 संरचना का स्थान 5+3+3+4 पाठ्यचर्या ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना:

| Stage        | Classes               | Age Group   | Focus Areas                                 |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Foundational | Pre-school to Class 2 | 3–8 years   | Play-based, activity-driven learning        |
| Preparatory  | Classes 3–5           | 8–11 years  | Discovery-based, interactive learning       |
| Middle       | Classes 6–8           | 11–14 years | Experiential learning, critical thinking    |
| Secondary    | Classes 9–12          | 14–18 years | Multidisciplinary, flexible subject choices |

शिक्षक इन सुधारों के केंद्र में हैं। इसे पहचानते हुए, छत्तीसगढ़ निरंतर व्यावसायिक विकास में भारी निवेश कर रहा है। नए डिजिटल उपकरणों में महारत हासिल करने से लेकर समावेशी शिक्षा प्रथाओं को अपनाने तक, शिक्षकों को केवल ज्ञान देने वाले के बजाय सीखने के सूत्रधार के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वितरित करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक पीछे न रहें। पाठ्यक्रम सह-निर्माण, प्रतिक्रिया तंत्र और नेतृत्व के अवसरों के माध्यम से शिक्षकों का सशक्तिकरण NEP की परिवर्तनकारी क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी एकीकरण फोकस के अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। राज्य स्मार्ट शिक्षाओं के विकास, ई-लर्निंग सामग्री के वितरण और तकनीक-आधारित शिक्षाशास्त्र में शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए काम कर रहा है। दीक्षा और ई-पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भर के छात्रों को भौगोलिक दृष्टि से परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण सामग्री तक पहुंच प्राप्त हो। कोविड-19 महामारी के बाद इन प्रयासों को विशेष महत्व मिला, जिसने लचीली और अनुकूल शैक्षिक प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

एनईपी 2020 का एक आधारभूत स्तंभ गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक सार्वभौमिक पहुंच है। छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी केंद्रों को अच्छी तरह से सुसज्जित पूर्व-प्राथमिक संस्थानों में बदलने के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें साक्षरता, संख्यात्मकता, मोटर कौशल और सामाजिक-भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ईसीसीई पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण घटक शामिल हैं, जो बच्चों की शैक्षिक यात्रा की समग्र शुरुआत सुनिश्चित करते हैं। इन केंद्रों में शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और खेल-आधारित शिक्षण तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि एक पोषण वातावरण बनाया जा सके।

व्यावसायिक शिक्षा एनईपी का एक और गेम-चेंजिंग घटक है। छत्तीसगढ़ शिक्षा 6 से ही छात्रों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें कृषि, आईटी, बर्द्धग्री और स्थानीय शिल्प जैसे क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थानीय उद्योग जगत के नेताओं, कारीगरों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी शिक्षा और रोजगार के बीच एक पाइपलाइन बनाने में मदद कर रही है। ये व्यावसायिक मांड्यूल व्यावहारिक हैं, जो छात्रों को

जीवन में कम से कम समय में ही करियर के रास्ते तलाशने की अनुमति देते हैं, साथ ही व्यावहारिक समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं।

भाषा नीति को भी नया रूप दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़, अपने व वध भाषाई परिदृश्य के साथ, कम से कम ग्रेड 5 तक छात्रों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। इस बदलाव को द्विभाषी शिक्षण संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास द्वारा समर्थित किया जा रहा है। यह पहल न केवल समझ में सुधार करती है बल्कि किसी की सांस्कृतिक वरासत पर गर्व भी बढ़ाती है। उच्च स्तरों पर, आवश्यकतानुसार हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में सहज संक्रमण को सक्षम करने के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहित किया जाता है। समावेशता छत्तीसगढ़ के एनईपी कार्यान्वयन के मूल में है। राज्य लड़कियों, वकलांग बच्चों और हाशिए के समुदायों के छात्रों को समायोजित करने वाले बुनियादी ढाँचे को प्रदान करके असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उपायों में लंग-संवेदनशील स्वच्छता सुवधाएँ, सहायक शिक्षण उपकरण और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए अनुरूप शिक्षण अभ्यास शामिल हैं। मध्याह्न भोजन योजनाओं, परिवहन सुवधाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से ड्रॉपआउट दरों को रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ समकालीन वषयों और जीवन कौशल को पाठ्यक्रम में एकीकृत कर रहा है। माध्यमिक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोडिंग, पर्यावरण विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और वृत्तीय साक्षरता जैसे वषय पेश किए जा रहे हैं। ये अतिरिक्त सुवधाएँ छात्रों को ऐसी योग्यताएँ प्रदान करती हैं जो उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं, जिससे शिक्षा आकांक्षापूर्ण और लागू करने योग्य दोनों बनती है। राज्य रचनात्मकता, वैज्ञानिक जाँच और नैतिक तर्क पर जोर दे रहा है, जो स्वतंत्र विचारकों की एक पीढ़ी के लिए आधार तैयार कर रहा है।

NEP पारंपरिक वषय साइलो को तोड़ने को भी प्रोत्साहित करता है। माध्यमिक स्तर के छात्र अब बाधाओं के बजाय रुचि के आधार पर कला, विज्ञान और वाणिज्य के संयोजन चुन सकते हैं। वषय चयन में यह लचीलापन एक मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा प्रारूप के साथ है, जो छात्रों को प्रबंधनीय खंडों में परीक्षा देने और समय के साथ स्कोर में सुधार करने की अनुमति देता है। इस तरह के लचीलेपन का उद्देश्य सीखने की गहराई और व्यक्तिगत पसंद को बढ़ावा देते हुए शिक्षणक दबाव को कम करना है।

सामुदायिक भागीदारी एक और स्तंभ है जिसे NEP 2020 मजबूत करता है। छत्तीसगढ़ स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) की भूमिका को बढ़ा रहा है, जिससे माता-पिता, स्थानीय नेता और शिक्षक स्कूल के विकास को आकार देने में एक साथ काम कर सकें। स्कूल क्लस्टर बनाकर, राज्य पड़ोसी संस्थानों के बीच संसाधन साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह वकेंद्रीकरण स्कूलों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित रहते हुए स्थानीय स्तर पर नवाचार करने का अधिकार देता है। NEP 2020 छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली में एक शांत क्रांति को उत्प्रेरित कर रहा है। आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाने वाली कक्षाओं से लेकर AI और माइंडफुलनेस सिखाने वाले पाठ्यक्रम तक, परिवर्तन व्यापक है। NEP 2020 को लागू करने के लिए राज्य का दृष्टिकोण अपनी विशेष पहचान को बनाए रखने और अपने बच्चों को वैश्विक भविष्य के लिए तैयार करने के बीच संतुलन को दर्शाता है। सफलता का पैमाना केवल परीक्षा के अंकों में नहीं होगा, बल्कि इस बात में भी होगा कि क्या प्रत्येक बच्चा अपने सीखने के माहौल में जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और देखभाल महसूस करता है। NEP 2020 के लेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक समानता और उत्कृष्टता की यात्रा में एक उम्मीद भरा अध्याय लिख रहा है।

### **छत्तीसगढ़ में शिक्षा की पुनर्कल्पना: एनईपी 2020 इन एक्शन (2025-26)**

शिक्षणक सत्र 2025-26 छत्तीसगढ़ के शिक्षक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को तेज कर रहा है। समग्र विकास, लचीलेपन और समावेशता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनईपी का उद्देश्य पूरे राज्य में छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को नया रूप देना है। छत्तीसगढ़, अपने व वध

जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिदृश्य के साथ, नवाचार और क्षेत्रीय प्रासंगिकता के मश्रण के साथ इस बदलाव को अपना रहा है।

#### 1. 5+3+3+4 मॉडल में संरचनात्मक बदलाव

सबसे अधिक दिखाई देने वाले सुधारों में से एक पारंपरिक 10+2 प्रणाली की जगह नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना को अपनाना है। यह मॉडल स्कूली शिक्षा को चार चरणों में विभाजित करता है:

1. **आधारभूत चरण (3-8 वर्ष):** इसमें प्री-प्राइमरी और कक्षा 1-2 के तीन वर्ष शामिल हैं, जिसमें खेल-आधारित और गतिविधि-संचालित सीखने पर जोर दिया जाता है।
2. **प्रारंभिक चरण (8-11 वर्ष):** कक्षा 3-5 में खोज और अंतःक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
3. **मध्य चरण (11-14 वर्ष):** कक्षा 6-8 में अनुभवात्मक शिक्षण और अमूर्त सोच का परिचय दिया जाता है।
4. **माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष):** कक्षा 9-12 में बहु-विषयक अध्ययन और लचीले विषय विकल्प दिए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ ने पहले ही इस मॉडल के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण का पुनर्गठन शुरू कर दिया है, जिससे चरणों और आयु-उपयुक्त शिक्षण के बीच सहज संक्रमण सुनिश्चित हो सके।

#### 2. शिक्षणक निरंतरता के लिए ब्रिज कोर्स

2025-26 से शुरू होकर, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। ये अल्पकालिक मॉड्यूल पहले शिक्षणक वर्ष की मूलभूत अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे छात्रों को नई सामग्री में आसानी से संक्रमण करने में मदद मिलती है। पाठ्यक्रम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और सीखने के अंतराल और शिक्षणक तनाव को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।

#### 3. लचीली बोर्ड परीक्षाएँ

2025-26 में प्रभावी होने वाला एक बड़ा सुधार यह है कि छात्रों के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएँ साल में दो बार देने का विकल्प है। यह लचीलापन छात्रों को एक ही उच्च-दांव परीक्षा के दबाव के बिना अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति देता है। परीक्षाएँ मॉड्यूलर होंगी, सीखने की छोटी इकाइयों का परीक्षण करेंगी और छात्र अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर को बनाए रख सकते हैं। इस बदलाव से परीक्षा की चंता कम होने और गहरी समझ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

#### 4. पाठ्यक्रम का नया स्वरूप और पाठ्यपुस्तक नवाचार

एनईपी 2020 के साथ संरेखित, छत्तीसगढ़ कक्षा 3 और 6 के लिए संशोधित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें शुरू कर रहा है। ये नए संस्करण इस बात पर जोर देते हैं:

1. गतिविधि-आधारित शिक्षा
2. जीवन कौशल विकास
3. परियोजना-आधारित मूल्यांकन
4. स्थानीय आदिवासी ज्ञान और संस्कृति का एकीकरण

राज्य की अनूठी विरासत को दर्शाने के लिए पाठ्यक्रम को स्थानीय बनाया जा रहा है, जिससे विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए सीखना अधिक प्रासंगिक और समावेशी हो सके।



## 5. योग्यता-आधारित मूल्यांकन

पारंपरिक रटने-आधारित मूल्यांकन की जगह योग्यता-आधारित मूल्यांकन को लाया जा रहा है। स्कूल समग्र प्रगति कार्ड अपना रहे हैं जो छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन, सह-पाठ्यचर्या भागीदारी और सामाजिक-भावनात्मक विकास के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। ये कार्ड छात्रों के विकास का 360-डिग्री दृश्य प्रदान करते हैं, जो समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं।

## 6. कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा

कौशल विकास पर NEP के जोर के अनुरूप, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जा रही है। छात्र कृषि, बढ़ईगरी, आईटी और स्थानीय शिल्प जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल का पता लगाएंगे। छत्तीसगढ़ स्थानीय उद्योगों और कारीगरों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए तैयार किया जा सके।

## 7. बहुभाषावाद और मातृभाषा शिक्षण

छत्तीसगढ़ कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षण को बढ़ावा दे रहा है। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में द्विभाषी शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही है। यह दृष्टिकोण समझ को बढ़ाता है और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देता है, साथ ही उच्च ग्रेड में हिंदी या अंग्रेजी में बदलाव को भी आसान बनाता है।

## 8. प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

राज्य आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में अपग्रेड कर रहा है, उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत कर रहा है। ईसीसीई पाठ्यक्रम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, मोटर कौशल और भावनात्मक विकास पर केंद्रित है। युवा शिक्षार्थियों के लिए एक पोषण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को खेल-आधारित शिक्षाशास्त्र और बाल मनोविज्ञान में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

## 9. डिजिटल लर्निंग और इंफ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए, छत्तीसगढ़ स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल सामग्री और दीक्षा और ई-पाठशाला जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच का विस्तार कर रहा है। शिक्षकों को डिजिटल टूल और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में छात्र डिजिटल युग में पीछे न रहें।

## 10. शिक्षक सशक्तीकरण और प्रशिक्षण

शिक्षक NEP की सफलता के केंद्र में हैं। 2025-26 में, छत्तीसगढ़ सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रमों को बढ़ा रहा है। शिक्षकों को निम्नलिखित में प्रशिक्षित किया जा रहा है:

1. योग्यता-आधारित शिक्षाशास्त्र
2. समावेशी शिक्षा अभ्यास
3. डिजिटल टूल का उपयोग
4. पाठ्यक्रम सह-निर्माण

ये पहल शिक्षकों को केवल सामग्री वितरित करने के बजाय सीखने के सूत्रधार बनने के लिए सशक्त बनाती हैं।

## 11. समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा

छत्तीसगढ़ यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, खासकर हाथ पर पड़े समुदायों के लिए। मुख्य उपायों में शामिल हैं:

1. लंग-संवेदनशील बुनियादी ढाँचा (जैसे, लड़कियों के लिए अलग शौचालय)

2. वकलांग बच्चों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियाँ

3. आदिवासी और ग्रामीण छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान

राज्य मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, परामर्श सेवाओं और माइंडफुलनेस प्रथाओं को स्कूल की दिनचर्या में एकीकृत कर रहा है।

## 12. समकालीन वर्षों का एकीकरण

छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, पाठ्यक्रम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, पर्यावरण शिक्षा और वृत्तीय साक्षरता शामिल हैं। इन वर्षों को माध्यमिक स्तर पर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए पेश किया जा रहा है।

## 13. छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल

पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत, छत्तीसगढ़ में 211 स्कूलों को मॉडल संस्थानों के रूप में सेवा देने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। ये स्कूल शिक्षण, बुनियादी ढांचे और शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेंगे, जो नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करेंगे।

## 14. सामुदायिक भागीदारी और स्कूल प्रशासन

एनईपी 2020 वकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। छत्तीसगढ़ स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को मजबूत कर रहा है और संसाधन साझा करने के लिए स्कूल क्लस्टर को बढ़ावा दे रहा है। माता-पिता, स्थानीय नेताओं और शिक्षकों को स्कूल विकास योजनाओं को आकार देने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2025-26 का शैक्षणिक सत्र छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। एनईपी 2020 को अपने मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में लेकर, राज्य स्कूली शिक्षा के एक शिक्षार्थी-केंद्रित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार मॉडल की ओर बढ़ रहा है। लचीली परीक्षाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण से लेकर डिजिटल कक्षाओं और मातृभाषा शिक्षण तक, परिवर्तन संरचनात्मक और सांस्कृतिक दोनों हैं। ये सुधार जड़ पकड़ते हैं, अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ छत्तीसगढ़ का हर बच्चा - पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना - खुशी से सीख सके, आत्मविश्वास के साथ बढ़ सके और तेजी से बदलती दुनिया में पनप सके।

## निष्कर्ष –

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन राज्य की शैक्षिक यात्रा में एक परिवर्तनकारी अध्याय है। पछले पाँच वर्षों में, राज्य ने समानता, गुणवत्ता और लचीलेपन के NEP के दृष्टिकोण के साथ स्कूली शिक्षा को फर से परिभाषित करने के लिए एक सराहनीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह निष्कर्ष अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को संश्लेषित करता है और नीति, अभ्यास और भविष्य के अनुसंधान के लिए व्यापक निहितार्थों को दर्शाता है।

सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक पारंपरिक 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 मॉडल में संरचनात्मक बदलाव रहा है। इस पुनर्गठन ने शुरुआती वर्षों में बुनियादी शिक्षा पर जोर देते हुए उम्र के हिसाब से उपयुक्त शिक्षाशास्त्र की अनुमति दी है। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE) को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया है कि बच्चे आवश्यक संज्ञानात्मक और सामाजिक-भावनात्मक कौशल के साथ प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करें। मशिन-मोड कार्यक्रमों और ब्रिज कोर्स द्वारा समर्थित मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राज्य के फोकस ने, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी जिलों में, सीखने के परिणामों में मापनीय सुधार लाना शुरू कर दिया है।

पाठ्यक्रम सुधार छत्तीसगढ़ की NEP यात्रा का एक और आधार रहा है। आदिवासी लोककथाओं, क्षेत्रीय इतिहास और पर्यावरण वर्षों को शामिल करने वाली स्थानीय पाठ्यपुस्तकों के विकास ने सीखने को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक

बना दिया है। योग्यता-आधारित सीखने और आकलन की ओर बदलाव ने रटने से ध्यान हटाकर वैचारिक समझ और अनुप्रयोग पर केंद्रित कर दिया है। समग्र प्रगति कार्ड, जो अब व्यापक रूप से अपनाए जा रहे हैं, छात्र विकास की एक अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं, जिसमें शैक्षणिक, सह-पाठ्यचर्या और भावनात्मक आयाम शामिल हैं। शिक्षक सशक्तिकरण ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, शिक्षकों को नए शैक्षणिक उपकरण, डिजिटल दक्षताओं और समावेशी प्रथाओं से लैस किया गया है। शिक्षक शिक्षण केंद्रों और सहकर्मी सलाह नेटवर्क की स्थापना ने सहयोग और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हालांकि, अध्ययन में निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की रिक्तियां और प्रशिक्षण अंतराल चंता का वषय बने हुए हैं।

डिजिटल शिक्षा एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में उभरी है। जबकि राज्य ने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने और DIKSHA जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में प्रगति की है, इंटरनेट एक्सेस और डिवाइस उपलब्धता में असमानताएँ समान शिक्षा में बाधा डालती हैं। डिजिटल विभाजन विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्पष्ट है, जहाँ बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ और भाषा बाधाएँ अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इन अंतरालों को संबोधित करने के लिए लक्षित निवेश, सामुदायिक जुड़ाव और ऑफलाइन डिजिटल संसाधनों के विकास की आवश्यकता होगी। कक्षा 6 से शुरू की गई व्यावसायिक शिक्षा ने छात्रों के लिए व्यावहारिक कौशल और करियर विकल्पों का पता लगाने के लिए नए रास्ते खोले हैं। स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग ने सीखने के अनुभव को समृद्ध किया है और रोजगार क्षमता को बढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वृत्तीय साक्षरता और पर्यावरण अध्ययन जैसे समकालीन विषयों को शामिल करना छात्रों को तेजी से विकसित हो रही दुनिया के लिए तैयार करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बहुभाषीवाद को एक बाधा के बजाय एक शैक्षणिक ताकत के रूप में अपनाया गया है। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण को बढ़ावा देने और द्विभाषी शिक्षण सामग्री विकसित करके, छत्तीसगढ़ ने शिक्षार्थियों के बीच समझ और सांस्कृतिक गौरव में सुधार किया है। इस दृष्टिकोण ने उच्च कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी में सहज संक्रमण की सुविधा भी प्रदान की है, जिससे शैक्षणिक निरंतरता का समर्थन हुआ है।

NEP कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान समावेशीता एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। राज्य ने लंग-संवेदनशील बुनियादी ढाँचे, वकलांग बच्चों के लिए सहायक तकनीकों और हाथ के समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी है। विशेष रूप से लड़कियों और आदिवासी छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दरों को कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। फिर भी, अध्ययन निरंतर निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा पर NEP 2020 का प्रभाव गहरा और बहुआयामी दोनों रहा है। नीति अपनाने से लेकर प्रणालीगत परिवर्तन तक राज्य की यात्रा विविध संदर्भों में शिक्षक सुधार की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में मूल्यवान् अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, आगे की राह निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, वृत्तीय प्रतिबद्धता और जमीनी स्तर पर नवाचार की मांग करती है। जिज्ञासा, करुणा और आलोचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देकर, छत्तीसगढ़ न केवल अपनी कक्षाओं को नया स्वरूप दे रहा है, बल्कि 21वीं सदी में सफल होने के लिए तैयार शिक्षार्थियों की एक पीढ़ी का पोषण भी कर रहा है।

#### Reference List :

1. Government of India. (2020). [National Education Policy 2020](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf). Ministry of Education.
2. Ministry of Education. (2023). [UDISE+ 2022-23: School Education in India](https://udiseplus.gov.in). Department of School Education & Literacy.
3. National Council of Educational Research and Training. (2023). [National Curriculum Framework for School Education \(NCF-SE\)](https://ncf.ncert.gov.in).
4. Chhattisgarh Council of Educational Research and Training. (2022). [Annual Report on NEP Implementation in Chhattisgarh](#). Raipur: SCERT Chhattisgarh.

5. Central Square Foundation. (2023). [NEP Implementation Tracker: State-wise Progress Report](https://www.centralsquarefoundation.org/reports/nep-tracker-2023). <https://www.centralsquarefoundation.org/reports/nep-tracker-2023>
6. National Council for Teacher Education. (2021). [Guidelines for Teacher Education under NEP 2020](https://ncte.gov.in). <https://ncte.gov.in>
7. Ministry of Education. (2021). [Foundational Literacy and Numeracy: Mission Guidelines](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/FLN_Guidelines.pdf). [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/FLN\\_Guidelines.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/FLN_Guidelines.pdf)
8. Chhattisgarh School Education Department. (2023). [Samagra Shiksha Annual Report 2022–23](#). Raipur: Government of Chhattisgarh.
9. UNESCO. (2021). [Education for Sustainable Development in India: Policy and Practice](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377455). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377455>
10. National Institute of Educational Planning and Administration. (2022). [School Leadership and Governance in NEP 2020](https://niepa.ac.in). <https://niepa.ac.in>
11. Azim Premji Foundation. (2022). [Understanding NEP 2020: Implications for School Education](https://azimpremjifoundation.org). <https://azimpremjifoundation.org>
12. UNICEF India. (2023). [Equity and Inclusion in Indian Education: A State-Level Analysis](https://www.unicef.org/india/reports). <https://www.unicef.org/india/reports>
13. National Digital Education Architecture (NDEAR). (2022). [Blueprint for Digital Transformation in Education](https://ndear.gov.in). <https://ndear.gov.in>
14. National Education Alliance for Technology (NEAT). (2023). [EdTech in Indian Classrooms: A Policy Perspective](https://neat.aicte-india.org). <https://neat.aicte-india.org>
15. Pratham Education Foundation. (2023). [Annual Status of Education Report \(ASER\) 2023](https://www.asercentre.org). <https://www.asercentre.org>
16. Mehrotra, D. (2021). [NEP 2020 – At a glance for educators: Towards excellence](#). Notion Press.
17. Sharma, R. (2020). [Review of National Education Policy 2020 with specific reference to school education](#). VOR Research.
18. NCERT. (2023). [National curriculum framework for school education \(NCF-SE\)](#). National Council of Educational Research and Training.
19. Ministry of Education. (2020). [National Education Policy 2020](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf). Government of India. [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/NEP\\_Final\\_English\\_0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)
20. Kumar, K. (2021). [Education, state and policy: The politics of education in India](#). Routledge India.
21. Tilak, J. B. G. (2021). [Education and development: Policy, planning and governance](#). Springer.
22. Singh, A. (2022). [Understanding NEP 2020: A critical perspective](#). Sage Publications.
23. Pathak, R. P. (2021). [Educational reforms in India: Issues and challenges](#). Pearson Education India.
24. Gupta, D. (2022). [School education in India: Policy, practice and prospects](#). Atlantic Publishers.
25. Azim Premji Foundation. (2022). [Understanding NEP 2020: Implications for school education](#). Azim Premji University.